गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 233
दि. 24.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

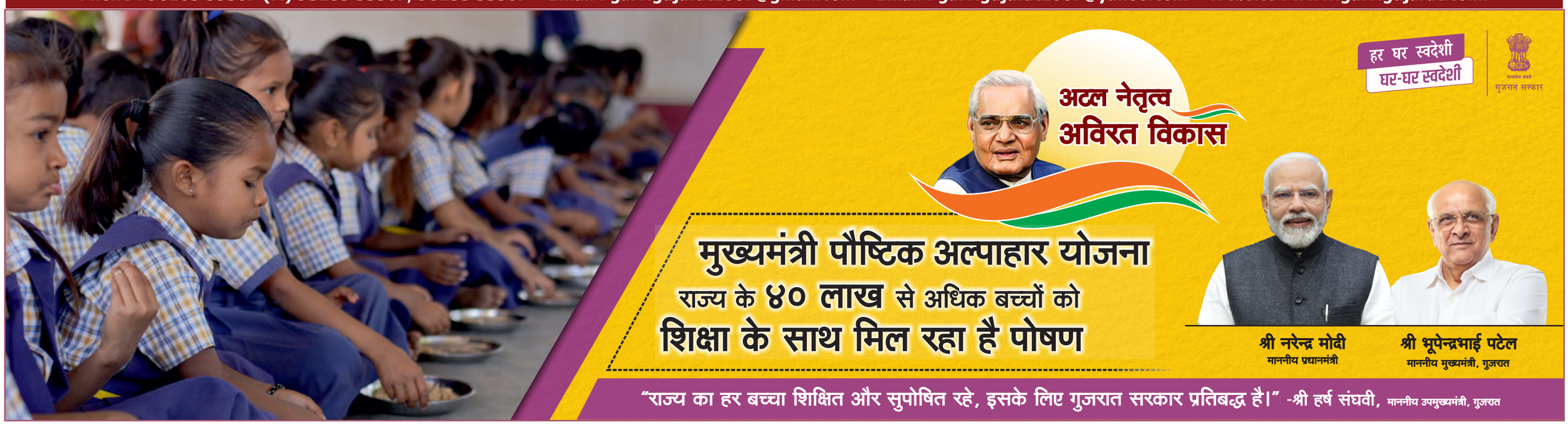

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का पुलिस और प्रजा के बीच विश्वास का सेतु अधिक सुदृढ़ हो तथा प्रजा का पुलिस पर भरोसा ठोस बने; ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रेरक आह्वान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्राइम कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराया

▸▸ गुजरात पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अलावा क्राइम डिटेक्शन-प्रिवेंशन तथा कम्युनिटी आउटरीच सहित सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर रही है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ उप मुख्यमंत्री का जूनियर आईपीएस अधिकारियों से लेकर सीनियर आईपीएस अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नए विषयों और बेस्ट प्रैक्टिसेज को उदार मन से स्वीकार करने का अनुरोध

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे पुलिस और प्रजा के बीच विश्वास का सेतु सुदृढ़ हो तथा प्रजा को पुलिस के साथ जुड़ने में कोई तकलीफ न रहे; ऐसे ठोस वातावरण का निर्माण करें।

उन्होंने कहा कि प्रजा के साथ सुदृढ़ संपर्क तथा प्रजा का पुलिस पर विश्वास ही क्राइम कंट्रोल के लिए हमारी आईबी है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि गुजरात में जो शांति एवं सुरक्षा है, उसके परिणामस्वरूप हमने विकास के रोल मॉडल राज्य के रूप में गौरव प्राप्त किया है। इतना ही नहीं; ग्लोबल कंपनियाँ और उद्योग भी राज्य की इस शांति एवं सुरक्षा की स्थिति के कारण ही व्यापार-उद्योग के लिए गुजरात का चयन करती हैं।

उन्होंने इसका श्रेय राज्य पुलिस की सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा तथा कर्तव्यभावना को देते हुए पुलिस बल को अभिनंदन दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में गांधीनगर में राज्य स्तरीय क्राइम कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ कराया। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में राज्य पुलिस महानिदेशक सहित अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक भाग ले रहे हैं।

श्री पटेल ने इस कॉन्फ्रेंस को राज्य की जनता के भले तथा सुरक्षा के लिए नया विचार-चिंतन-मंथन प्रदान करने वाला आयोजन बताया।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात पुलिस अपराध नियंत्रण एवं निवारण के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से सज्ज है, परंतु अपराध करने वाले भी अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस बेड़े में सतर्कता के साथ अधिक से अधिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक हुआ है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक में पुलिस बल में एआई का उपयोग, कोस्टल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम रोकने के श्रेष्ठ कार्य करने को लेकर भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस बल की जनोन्मुखी नीतियाँ और पुलिसिंग आदि व्यवस्थाएँ ठेठ ग्रामीण स्तर तक समान रूप से पहुँचें; यह भी वरिष्ठ अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अपेक्षा व्यक्त की कि पुलिस ड्रग्स की लत के शिकार हुए युवाओं को सजा के बजाय प्रेम से समझाकर काउंसेलिंग से सही रास्ते पर लाने की दिशा में भी कार्यरत रहेगी और बैठक में इस संबंध में फलदायी चिंतन-मंथन होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अलावा क्राइम डिटेक्शन-प्रिवेंशन तथा कम्युनिटी आउटरीच सहित सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर रही है। सामाजिक समस्याओं, असामाजिक तत्वों तथा साइबर अपराधियों के विरुद्ध गुजरात ने बाकायदा हल्लाबोल करके अद्भुत कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने गुजरात पुलिस की समग्र टीम को अभिनंदन दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸ गुजरात देश के विकास का रोल मॉडल बना, जिसकी नींव शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने वाले पुलिस बल की कर्तव्यनिष्ठा है

▸▸ एआई सहित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज तथा सतर्क पुलिस बल अपराधियों द्वारा टेक्नोलॉजी के उपयोग से होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए सक्षम है

श्री संघवी ने दो दिवसीय क्राइम कॉन्फ्रेंस के दौरान जूनियर आईपीएस अधिकारियों से लेकर सीनियर आईपीएस अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नए विषयों और बेस्ट प्रैक्टिसेज को उदार मन से स्वीकार करने का आह्वान करते हुए जोड़ा कि जब इस राष्ट्रीय स्तर की क्राइम कॉन्फ्रेंस के आयोजन का विचार किया गया, तब सभी शहर/जिले के डीसीपी/एसपी स्तरीय अधिकारियों का भी समावेश करने पर बल दिया गया, जिससे इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके आइडिया साझा हों और उनके द्वारा किए जा रहे टेक्नोलॉजी के उपयोग तथा अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए नए प्रयासों का आपसी आदान-प्रदान हो।

राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि राज्य में आयोजित होने वाली क्राइम कॉन्फ्रेंसेज का बहुत ही महत्व है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता तथा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित हुई डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी डाउन द लाइन फील्ड ऑफिसर तक पहुँचे; इसके लिए भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। इसके अलावा; बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम डिटेक्शन-प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन तथा ऑपरेशन सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

राज्य पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय ने कहा कि क्लोज को-ऑर्डिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में सभी शहर, रेंज के विभिन्न जिलों द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेज के संबंध में प्रेजेंटेशन के साथ आवश्यक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा; साइबर क्राइम, नारकोटिक्स सहित वर्तमान चुनौतियों तथा उनके निवारण पर भी गहन चर्चा की जाएगी। गुजरात पुलिस की हर इकाई में श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, जो प्रशंसनीय है। फिर भी हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश रहती है, जो तभी हो सकता है, जब आत्ममंथन तथा समीक्षा हो और इस समीक्षा तथा आत्ममनंथन के लिए क्राइम कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है।

इस अवसर पर सीआईडी क्राइम डीजीपी डॉ. के. एन. एल. राव, श्री जी. एस. मलिक, डॉ. नीरजा गोटरू सहित डीजीपी रैंक के अधिकारी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी तथा एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारी उपस्थित रहे।

बर्लिन में राहुल गांधी के बयान से सियासी भूचाल 'वोट चोरी' के आरोप पर BJP का तीखा हमला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों ने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। हर्टी स्कूल में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को कमजोर करने और चुनावी प्रक्रिया में कथित तौर पर छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उनके इन बयानों के सामने आते ही भारतीय राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है और BJP ने इसे विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत चुकी थी, लेकिन परिणाम बदल दिए गए। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वहां की चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। राहुल ने यह भी कहा कि देश में करोड़ों लोग सरकार और RSS की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से इस पूरे संवाद का लगभग एक घंटे का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें राहुल गांधी वही आरोप दोहराते नजर आ रहे हैं, जो वह लगातार देश के भीतर भी उठाते रहे हैं।

राहुल गांधी के इस बयान के बाद BJP ने तीखा पलटवार किया। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र और संस्थानों को बदनाम कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक ओर पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व और सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने में लगे हैं।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश की संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान विदेश जाकर इस तरह के बयान देना गैरजिम्मेदाराना है और इससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर और भी तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल की तुलना मीर जाफर से करते हुए आरोप लगाया कि वह देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। BJP नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का यह रवैया भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।

इस विवाद में BJP ने 'सोरोस कनेक्शन' का मुद्दा भी उठाया है। पार्टी का दावा है कि हर्टी स्कूल की प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल का संबंध अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से है। BJP का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस भारत में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी हुई है। BJP नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी का विदेश में इस मंच से ऐसे बयान देना इसी साजिश का हिस्सा है।

जंक फूड की लत ने छीन ली 11वीं की छात्रा की जिंदगी, एम्स की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। फास्ट फूड और जंक फूड के बढ़ते चलन के बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से सामने आया यह मामला पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरा है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज के दौरान हो गई। डॉक्टरों की प्रारंभिक रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण लंबे समय तक अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन बताया गया है। इस घटना ने न केवल परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि बच्चों और किशोरों के खानपान को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मृत छात्रा अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के अफगान मोहल्ले की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार उसे चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड खाने की आदत थी और वह अक्सर घर के बने भोजन की जगह जंक फूड को ही प्राथमिकता देती थी। पिछले कुछ समय से उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। पेट दर्द, कमजोरी और अन्य समस्याओं के चलते पहले उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। एम्स में जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि छात्रा की आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। चिकित्सकों के मुताबिक लंबे समय तक अत्यधिक फास्ट फूड खाने से उसकी पाचन प्रणाली पर बुरा असर पड़ा था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि आंतों को साफ करने के लिए सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर छात्रा की जान नहीं बचा सके। प्रारंभिक चिकित्सकीय आकलन में फास्ट फूड को ही उसकी मौत का मुख्य कारण माना गया है, हालांकि विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट की प्रक्रिया जारी है। इस दुखद घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। माता-पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं और उनका कहना है कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि बच्चों की पसंदीदा समझी जाने वाली ये चीजें इतनी घातक साबित हो सकती हैं। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर शोक और चिंता का माहौल है। क्षेत्र के कई लोगों का कहना है कि यह मामला आंखें खोलने वाला है और इससे सबक लेने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों और किशोरों में जंक फूड की बढ़ती लत बेहद खतरनाक होती जा रही है। फास्ट फूड में पोषक तत्वों की कमी और अत्यधिक वसा, नमक व रसायनों की मौजूदगी शरीर के अंदर धीरे-धीरे गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआत में इसके दुष्परिणाम नजर नहीं आते, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन जानलेवा साबित हो सकता है। यह मामला साफ तौर पर यह संकेत देता है कि बच्चों और किशोरों के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार कितना जरूरी है। चिकित्सकों और सामाजिक संगठनों ने परिवारों और स्कूलों से अपील की है कि वे बच्चों की खानपान की आदतों पर विशेष ध्यान दें। जंक फूड के प्रति जागरूकता फैलाने, इसके सेवन को सीमित करने और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाना अब समय की जरूरत बन गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके।

नमो भारत ट्रेन में अशोभनीय कृत्य से मचा हड़कंप, वायरल वीडियो के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

(जीएनएस)। गाजियाबाद। देश की आधुनिक रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन से जुड़ा एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद में संचालित नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच के भीतर युवक और युवती द्वारा कथित तौर पर अश्लील हरकत किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुरादनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। इस घटना ने न केवल सार्वजनिक परिवहन की मर्यादा और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा की है। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार यह घटना 24 नवंबर 2025 की बताई जा रही है। उस दिन नमो भारत ट्रेन संख्या 23 दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही थी। आरोप है कि ट्रेन के प्रीमियम कोच में यात्रा कर रहे एक युवक और एक युवती ने सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कृत्य किया, जिससे यात्रियों की शालीनता, सामाजिक मर्यादा और सार्वजनिक गरिमा को ठेस पहुंची। घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

मुरादनगर थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात युवक और युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 296 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया रही और क्या किसी ने तत्काल इसकी शिकायत की थी। इस पूरे मामले की शिकायत डीबीआरआरटीएस विभाग में सुरक्षा प्रमुख के पद पर तैनात दुष्यंत कुमार ने दर्ज कराई है। वह एनसीआरटीसी के तहत संचालित नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। उनकी शिकायत के आधार पर 22 दिसंबर 2025 की रात एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया है कि वायरल वीडियो से नमो भारत ट्रेन जैसी प्रीमियम सार्वजनिक परिवहन सेवा की छवि को नुकसान पहुंचा है और इससे यात्रियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।

जांच के दौरान एक और गंभीर पहलू सामने आया है। पुलिस के अनुसार ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ पर आरोप है कि उसने ड्यूटी के दौरान ऑपरेटर केबिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर इस घटना का वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह न केवल कंपनी के आंतरिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कानूनन भी एक गंभीर अपराध माना जा रहा है। सार्वजनिक सेवा में कार्यरत कर्मचारी द्वारा इस तरह की हरकत को सुरक्षा मानकों के खिलाफ बताया जा रहा है।

एनसीआरटीसी के तहत कार्यरत संबंधित कंपनी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी ऑपरेटर को 3 दिसंबर 2025 को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है, जो अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण से संबंधित है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि यात्रियों की गोपनीयता, सुरक्षा और गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की समानांतर जांच की जा रही है। वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी पड़ताल के साथ-साथ अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन, शालीनता और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला आने वाले समय में सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार और डिजिटल जिम्मेदारी को लेकर एक अहम मिसाल बन सकता है।

संपादकीय

जानलेवा आबोहवा

देश-दुनिया की निगाहें इन दिनों दिल्ली की हवा पर टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी है। हालांकि चर्चा का केंद्र दिल्ली बनी हुई है, लेकिन यह संकट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषण की गंभीर मार झेल रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर जैसे शहरों में भी प्रदूषण आम लोगों के स्वास्थ्य से खुला खिलवाड़ कर रहा है। भले ही इन शहरों में स्थिति दिल्ली जितनी भयावह न हो, लेकिन यह साफ संकेत है कि देश को प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक और समग्र नीति की सख्त जरूरत है।

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी दिल्ली में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सरकार को बार-बार आपात उपाय अपनाने पड़ रहे हैं। उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए, लेकिन इन सबके बावजूद हवा में जहर कम होता नहीं दिख रहा। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हम केवल अस्थायी उपायों के सहारे इस गंभीर समस्या से पार पा सकते हैं, या फिर हमें अपनी सोच और नीति दोनों को बदलना होगा।

इसी बीच चीन के दूतावास की ओर से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश ने एक नई बहस को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में दिल्ली का एक्यूआई 447 और बीजिंग का 67 दिखाया गया, जो अपने आप में चौंकाने वाला अंतर है। एक समय था जब सर्दियों में बीजिंग समेत चीन के कई शहर घने स्मॉग से ढके रहते थे और वहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं मानी जाती थी। लेकिन पिछले दो दशकों में चीन ने योजनाबद्ध और सख्त कदम उठाकर इस परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है। भारत और चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इसलिए चीन के अनुभवों से सीख लेना अनुचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह भी सच है कि साम्यवादी चीन और लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन की प्रकृति अलग-अलग है। फिर भी चीन ने प्रदूषण से निपटने के लिए जो ठोस कदम उठाए, वे नीति निर्माण के स्तर पर प्रेरणा दे सकते हैं। चीन ने आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया, वाहन उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण किया और लाइसेंस प्लेट लॉटरी व ऑड-ईवन जैसी व्यवस्थाओं के जरिए सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाई। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो और बस नेटवर्क का विस्तार किया गया, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही चीन ने सबसे कठिन लेकिन प्रभावी कदम उठाते हुए बीजिंग और आसपास के इलाकों से करीब तीन हजार भारी उद्योगों को बाहर स्थानांतरित किया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से ही खतरनाक कणों में लगभग बीस प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों और उद्योगों पर सख्त रोक लगाई गई, जो प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत माने जाते थे। निर्माण स्थलों पर धूल-रोधी जाली, नियमित पानी का छिड़काव, सड़कों की सफाई, किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए आर्थिक सहायता और प्रदूषण के चरम समय में निर्माण गतिविधियों पर रोक जैसे कदम भी निर्णायक साबित हुए। साथ ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया, जिससे पर्यावरण संतुलन में सुधार आया। दिल्ली और बीजिंग की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। दिल्ली एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और यहां समुद्री हवाओं का सहारा नहीं है, जिससे प्रदूषक कण लंबे समय तक वातावरण में टिके रहते हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि समाधान असंभव हैं। दिल्ली और उसके आसपास कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना, सार्वजनिक परिवहन को इतना सशक्त बनाना कि निजी वाहन स्वतः कम हों और औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर स्थानांतरित करना अब टाले जाने योग्य फैसले नहीं रहे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर विशेष बजट और स्पष्ट समयसीमा तय करनी होगी। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली की लगभग तीन सौ किलोमीटर की परिधि में ग्यारह कोयला आधारित पावर प्लांट मौजूद हैं, जिन्हें प्रदूषण का बड़ा स्रोत माना जाता है। जब तक इन संरचनात्मक कारणों पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक आपातकालीन उपाय केवल राहत भर देंगे, समाधान नहीं। प्रदूषण की समस्या अब केवल पर्यावरण की नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुकी है। इसलिए समय की मांग है कि दीर्घकालिक नीति बनाई जाए और उसे राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भारत की हवा दोबारा सांस लेने लायक बन सके।

राव की सोच की बुनियाद पर भारत बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था

> “ भारतीय अर्थव्यवस्था की उछाल इन दिनों दुनिया देख रही है। लेकिन पिछली सदी के अस्सी के दशक में अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी थी। हालात इतने बुरे थे कि भारत को अपना रिजर्व सोना बैंक ऑफ इंगलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। राव से ठीक पहले प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा, ‘ जीवन जैसा जिया’ में इस गिरवी प्रकरण की पूरी जानकारी दी है।

पामुलपार्थी वेंकट नरसिंह राव...यही पूरा नाम था उनका। आज ही के दिन ठीक इक्कीस साल पहले उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आखिरी सांस ली थी, जिसे देश के सबसे बेहतरीन सार्वजनिक अस्पताल माना जाता है। एम्स के नाम से विख्यात इस अस्पताल में जब उनकी आत्मा उनके शरीर रूपी पिंजरे से उड़ गई, तब देश में उन डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासन था, जिन्हें उन्होंने ही राजनीति की दुनिया में प्रवेश कराया था। राव कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण विदाई के हकदार थे। लेकिन उनकी ही पार्टी ने उन्हें यह विदाई मयस्सर नहीं होने दी और देश का प्रधानमंत्री भी मौन व्रत धारण किए रह गया। नेहरू, इंदिरा और राजीव को भारत रत्न देने वाली कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार ने अपने ही उस राव को उचित सम्मान देना उचित नहीं समझा, जिसके वे अध्यक्ष रह चुके थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की उछाल इन दिनों दुनिया देख रही है। लेकिन पिछली सदी के अस्सी के दशक में अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी थी। हालात इतने बुरे थे कि भारत को अपना रिजर्व सोना बैंक ऑफ इंगलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। राव से ठीक पहले प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा, ‘ जीवन जैसा जिया’ में इस गिरवी प्रकरण की पूरी जानकारी दी है। चंद्रशेखर के बाद एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बने राव के सामने तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुरी गत की जानकारी दी तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। ऐसे हालात में उनका विचलित होना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रोफेशनल अर्थशास्त्री को देश का वित्त मंत्री बनाने की सोची। उन्हें तब दो नाम सुझाए गए थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके आईजी पटेल और मनमोहन सिंह। राव

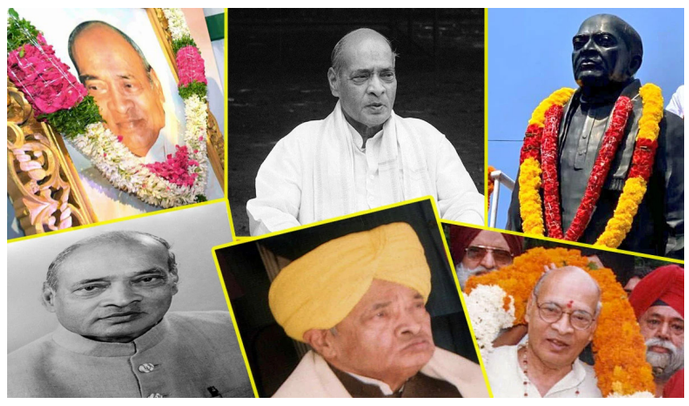

की पहली पसंद पटेल थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमार और बुजुर्ग मां की देखभाल के चलते वह जिम्मेदारी भरा पद लेना स्वीकार नहीं किया। नियति मनमोहन सिंह के पक्ष में थी। मनमोहन वित्त मंत्री बने। 1991 की 25 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। आर्थिक मोर्चे पर जारी लाइसेंस राज की विदाई की शुरूआत हुई। आर्थिक खुलेपन ने देश की आर्थिकी की जो नींव रखी, आज उसी नींव पर आगे बढ़ते हुए देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था का गौरव हासिल कर चुका है। बेशक यह सब मनमोहन सिंह की बदौलत हुआ। लेकिन अगर उनकी पीठ पर नरसिंह राव का हाथ नहीं होता तो क्या वे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल करने के लिए उद्यत हो सकते थे? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। भारत की आर्थिकी को मजबूत बुनियाद देने के साथ ही वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल के लिए तैयार करने में मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन बिना नरसिंह राव के मजबूत समर्थन के, वे ऐसे कदम नहीं उठा सकते थे। आज भारत की आर्थिकी की जो वैश्विक चमक दिख रही है, उसके असर नींव निर्माता नरसिंह राव ही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस कांग्रेस के वे नेता रहे, जिस कांग्रेस क साथ उन्होंने अपनी समूची राजनीतिक यात्रा पूरी की, उस कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया।

किनारा करने की वजह रहा बाबरी विध्वंस। छह दिसंबर 1992 को बाबरी का ध्वंस हुआ। ऐसा नहीं कि नरसिंह राव ने ध्वंस को रोकने की तैयारी नहीं की थी। गांधी-नेहरू परिवार के नजदीकी रहे पूर्व विदेश सेवा अधिकारी और कांग्रेसी राजनेता मणिशंकर अय्यर राव को इसी वजह से भाजपा का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं। बाबरी विध्वंस के बाद वामपंथी बौद्धिकों के एक खेमे ने उन्हें खाकी निक्कर वाला कहना शुरू कर दिया था। यहां याद दिलाना जरूरी है कि खाकी निक्कर कुछ साल पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की गणवेश होती थी। लेकिन नरसिंह राव ने अपने उपर लगे आरोपों का पुस्तक लिखकर जवाब दिया है. जो 2004 में उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई है। ‘अयोध्याः छह दिसंबर’ नामक यह पुस्तक साल 2006 में प्रकाशित हुई। इस किताब में एक तरह से राव ने बाबरी ध्वंस को लेकर उन पर लगने वाले अकर्मण्यता के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। इसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन और उससे पहले की घटनाओं, अपनी कार्रवाइयों और तब के राजनीतिक दबावों को लेकर पूरी जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में वे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा पाए। उन्होंने बताया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं थी और उनके सामने कई संवैधानिक चुनौतियां और बाधाएं भी थीं। इन तथ्यों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों मस्जिद को बचाने की उनकी कोशिशें किस तरह नाकाम रहीं। विनय सीतापति ने ’हाफ लायन’ नाम से राव की जीवनी लिखी है। इस पुस्तक में वे भी तमाम तथ्यों से साबित करने में सफल रहे हैं कि राव चाहकर भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे। अपनी किताब में राव ने तफसील से बताया है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अयोध्या पहुंच रहे कारसेवक शांतिपूर्ण हैं। राव ने साथ ही यह भी बताया है कि तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मस्जिद की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ऐसे में संवैधानिक मर्यादाओं और संघीय ढांचे के संवैधानिक प्रावधानों के कारण उनके हाथ बंधे हुए थे। राव ने अपनी पुस्तक में राम मंदिर आंदोलन के पीछे की राजनीतिक चालों और धार्मिक भावनाओं के दोहन के खतरों पर भी प्रकाश डाला गया है।

इसमें दो राय नहीं कि बाबरी ध्वंस के बाद कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह बदल गई। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान की जातीय कीमियागिरी के दम पर लंबे समय तक शासन में रही कांग्रेस का समर्थक आधार छीजने लगा। अल्पसंख्यकों ने कई प्रमुख राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से किनारा कर लिया। इसका असर कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति पर पड़ा। जिस समय बाबरी ध्वंस हुआ, उस समय गांधी-नेहरू परिवार राजनीति से दूर था। सोनिया गांधी तो सक्रिय राजनीति में 1998 में आईं। लेकिन उनके इशारे पर कांग्रेस का एक बड़ा खेमा काम करता रहा। अर्जुन सिंह, प्रियरंजन दास मुंशी, मणिशंकर अय्यर, प्रणब मुखर्जी आदि कांग्रेसी प्रथम परिवार के इशारे पर काम करते रहे। जब 1996 में कांग्रेस संसदीय चुनावों में हार गई तो नरसिंह राव को इस खेमे ने ना सिर्फ अप्रासंगिक बनाना शुरू किया, बल्कि उन्हें महत्वहीन भी बना दिया। कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 19884 में हुए सिख विरोधी हिंसा का भी दाग है। दिलचस्प यह है कि उस वक्त राजीव सरकार के गृहमंत्री नरसिंह राव ही थे। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। क्योंकि उसके साथ राजीव गांधी का वह बयान चिपका हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा से ग्रस्त पंजाब को पटरी पर लाने वाले नरसिंह राव ही थे। नरसिंह राव ने ही लुक ईस्ट नीति शुरू की और एशियायी देशों से भारत के मजबूत संबंध बनाने शुरू किए थे। लेकिन उनके इन योगदानों को भुला दिया गया। राव सिर्फ भारतीय आर्थिकी के ही शिल्पकार नहीं थे, बल्कि देश के आतंकग्रस्त इलाकों को सख्त प्रशासन और विकास कार्यों के समायोजन के जरिए मुख्यधारा में जोड़ने वाले रचनाकार भी रहे। मोदी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि उसने राजनीतिक कारणों से राव को 2024 में भारत रत्न दिया। लेकिन यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि राव का सम्मान भारत के बदलाव का दौर शुरू करने वाले शिल्पी का सम्मान है।

प्रेरणा

समर्पण से बहता हुआ आत्मिक मार्ग

संत ज्ञानेश्वर का जीवन केवल भक्ति और ज्ञान का उपदेश नहीं था, बल्कि वह हर छोटे दृश्य में जीवन का गूढ़ अर्थ खोज लेने की दिव्य दृष्टि का प्रतीक था। एक दिन की यह घटना भी कुछ ऐसी ही है, जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन भीतर से पूरे जीवन-दर्शन को खोलकर रख देती है। संत ज्ञानेश्वर अपने कुछ शिष्यों के साथ एक बाग के पास से गुजर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पौधों की पत्तियों पर धूप झिलमिला रही थी और एक माली शांत भाव से पौधों में पानी दे रहा था। पानी कभी नालियों में बहता, कभी जड़ों तक पहुंचता, कभी पत्तियों को छूकर नीचे गिर जाता। यह दृश्य बेहद साधारण था, लेकिन संत ज्ञानेश्वर की दृष्टि में यही दृश्य जीवन का सबसे बड़ा उपदेश बन गया।

उन्होंने अचानक रुककर शिष्यों से पूछा कि क्या वे पानी की विशेषता जानते हैं। शिष्य कुछ पल सोचते रहे। किसी ने कहा कि पानी जीवन देता है, किसी ने कहा कि पानी शीतलता देता है, किसी ने उसकी शुद्धता की बात की। संत ज्ञानेश्वर मुस्कराए। उन्होंने कहा कि ये सब बातें सही हैं, लेकिन पानी की सबसे बड़ी विशेषता कुछ और है। पानी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। वह न तो जिद करता है, न दिशा चुनता है, न यह तय करता है कि उसे कहां जाना है। माली जहां उसे बहाता है, पानी वहीं चला जाता है। न ऊंच-नीच की शिकायत, न रास्ते की कठिनाई की चिंता, न अपने अस्तित्व की कोई मांग। यही उसकी महानता है।

संत ने शिष्यों से कहा कि मनुष्य का जीवन इससे बिल्कुल उलट है। मनुष्य हर क्षण अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और योजनाओं में उलझा रहता है। वह चाहता है कि जीवन उसकी सोच के अनुसार चले, लोग उसकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें और परिस्थितियां उसके अनुकूल रहें। जब ऐसा नहीं होता, तो दुख, क्रोध, निराशा और भय जन्म लेते हैं। मनुष्य भूल जाता है कि वह इस विशाल सृष्टि में एक छोटी सी धारा है, और सृष्टि का माली स्वयं ईश्वर है। जब तक हम अपने को ही जीवन का नियंता मानते रहेंगे, तब तक अशांति बनी रहेगी।

उन्होंने समझाया कि पानी को देखो। वह पत्थर से टकराता है, लेकिन लड़ता नहीं। रास्ता बदल लेता है। कभी-कभी वही पानी धीरे-धीरे पत्थर को घिस देता है, बिना हिंसा के, बिना शोर के। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकना जानता है, वही टिकता है। जो समर्पण करना जानता है, वही आगे बढ़ता है। मनुष्य जब अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के हाथों में स्वयं को सौंप देता है, तब जीवन सहज हो जाता है। तब समस्याएं भी बोझ नहीं लगतीं, बल्कि सीख बन जाती हैं।

संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि ईश्वर को माली की तरह समझो। माली जानता है कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए, किसे धूप चाहिए और किसे छांव। अगर पानी खुद तय करने लगे कि वह किस पौधे को कितना मिलेगा, तो बाग उजड़ जाएगा। उसी तरह यदि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से यह तय करने लगे कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो जीवन में अव्यवस्था फैल जाती है। ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे है, लेकिन वह हमेशा हमारे कल्याण के लिए होती है। पानी की तरह यदि हम स्वयं को उसकी इच्छा में बहने दें, तो जीवन सुंदर, शांत और सार्थक बन सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। पानी बहता है, चलता है, जीवन देता है। वह जड़ नहीं होता। उसी तरह मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ। लेकिन कर्म के फल को लेकर आसक्ति न रखे। जैसे पानी फल की मांग नहीं करता, वैसे ही मनुष्य को भी परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है, यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है।

शिष्य इस उपदेश को सुनकर मौन हो गए। उन्हें पहली बार समझ में आया कि जीवन की सबसे बड़ी जटिलता का समाधान कितनी सरल बात में छिपा है। पानी जैसा जीवन जीना, यानी अहंकार छोड़ना, शिकायत छोड़ना, तुलना छोड़ना और स्वयं को ईश्वर की धारा में बहने देना। जब मनुष्य ऐसा करता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है।

संत ज्ञानेश्वर ने अंत में कहा कि जब जीवन में दुख आए, तो पानी बन जाना। जब सुख आए, तब भी पानी बन जाना। न दुख में कठोर होना, न सुख में अभिमान करना। जो हर स्थिति में बहना जान लेता है, वही मुक्त हो जाता है। यही पानी जैसा जीवन है, यही सच्ची साधना है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है।

समतामूलक समाज में ही आर्थिक न्याय संभव

भारत का नाम भले ही विश्व की सर्वाधिक तीव्रगति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है किंतु समानता के दृष्टिगत आज भी समाज में बृहद अंतर देखने को मिलता है। नवीनतम 'विश्व असमानता रिपोर्ट, 2026' की मानें तो, भारत की कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत (लगभग दो-तिहाई) हिस्सा शीर्ष 10 फ़ीसदी अमीरों के पास केंद्रित है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 6.4 प्रतिशत संपत्ति है। महिला श्रम भागीदारी दर सिर्फ 15.7 प्रतिशत है।

देश के टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है, जोकि 1961 के पश्चात सबसे ज्यादा आंकी गई। शीर्ष 10 प्रतिशत जहां राष्ट्रीय आय का 58 प्रतिशत कमाते हैं, वहीं निम्न 50 प्रतिशत लोगों को केवल 15 प्रतिशत आय मिलती है। 2014 से 2024 के बीच टॉप 10 प्रतिशत तथा नीचे के 50 प्रतिशत के बीच आय का अंतर थोड़ा बढ़कर, 38 प्रतिशत से 38.2 प्रतिशत हो गया।

आंकड़ों के तहत, भारत में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 6,200 यूरो तथा औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो है। रिपोर्ट भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में सम्मिलित करती है। असमानता दर, आर्थिक उदारीकरण के बाद तेज़ी से बढ़ी।

भारत सरकार के आंकड़े खंगालें तो अभी तक 41.32 प्रतिशत लोगों को आवास उपलब्ध नहीं। 31.52 प्रतिशत आबादी संतुलित पोषण से वंचित है हालांकि यही रिपोर्ट 24.82 करोड़ लोगों के ग़रीबी रेखा से ऊपर आने का दावा करती है। उपभोक्ता बाजार के अनुसार, प्रीमियम उत्पादों की मांग बढ़ना तथा अफोर्डेबल रियल एस्टेट सेगमेंट में गिरावट आना भी असमानता का सूचक है। आय व संपत्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के चलते अधिकांश लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हाशिए पर पड़े वर्ग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, नौकरियों आदि तक अपेक्षित पहुंच नहीं बना पाते।

उन्नत व पिछड़े राज्यों के बीच विकास का अंतर भी असमानता बढ़ाता है। विस्थापन के चलते लोगों को अपनी आजीविका तथा अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। भूमि स्वामित्व में असमानता तथा कृषि में अक्षमताएं ग्रामीण आय पर प्रभाव डालती हैं। पिछड़े क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच न होने से स्थानीय निवासियों की कमाई की क्षमता सिमटती है। देश की आबादी का एक बड़ा अंश कम मजदूरी तथा अस्थिर रोजगार वाले असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। कुशल व अकुशल श्रमिकों के बीच वेतन का भारी अंतर देखा गया। कई लोग अपनी योग्यता से कम काम करते हैं, जिसका उत्पादकता व आय, दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

वैश्वीकरण से वास्तव में असमानता को भी बढ़ावा मिला। विनिर्माण क्षेत्र में बाधाओं तथा सेवा क्षेत्र के लाभ कुछेक वर्गों तक सीमित होने की वज़ह से लाखों लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता जहां गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डालती है, वहीं असंगठित क्षेत्रों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ख़ासकर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें निम्न वर्ग की आय और भी कम कर देती हैं।

भारत में आय असमानता के मुख्य कारकों में शिक्षा-स्वास्थ्य तक असमान पहुंच, रोज़गार के अवसरों में अंतर, कौशल तथा वेतन में खाई, क्षेत्रीय असंतुलन, जाति-लिंग आधारित भेदभाव एवं धन का संकेंद्रण शामिल हैं। मुद्रास्फीति, अप्रभावी सरकारी नीतियों, सामाजिक न्याय के सिद्धांत लागू करने की विफलता, संसाधनों के वितरण व आर्थिक अवसरों में असमानता से अंतर और गहरा हो जाता है।

भारत में असमानता एक जटिल तथा व्यापक समस्या बनी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक़, इस असंतुलन का आर्थिक व सामाजिक ढांचे, दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ज़ाहिर है, अमीर-गरीब के मध्य बढ़ती खाई न केवल देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करती है बल्कि समाज में अशांति, असंतोष, पारस्परिक द्वेष तथा संघर्ष को भी जन्म देती है। रिपोर्ट के तथ्य हमारे राजनीतिज्ञों के आर्थिक-सामाजिक समता संबंधी वे तमाम दावे ख़ारिज करते प्रतीत होते हैं, जिनके आधार पर वे चुनावी वोट बैंक भुनाते दिखाई पड़ते हैं।

दरअसल, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की अवधारणा 'समतापरक समाज' के निर्माण पर ही टिकी है। समतावादी समाज का मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना रहा कि समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव समान अधिकार, अवसर तथा संसाधन प्राप्त हों। विशेषज्ञ भारत में धन के पुनर्वितरण, टैक्स न्याय के लिए व्यापक संपत्ति कर तथा सुपर टैक्स जैसे उपायों की वकालत करते हैं। सुनियोजन द्वारा समाज में मौजूद व्यापक अंतर निश्चय ही पाटा जा सकता है।

अभियान

आचरण की साधना से ग्रहों की शांति का गूढ़ रहस्य

मनुष्य के जीवन में ग्रहों का प्रभाव केवल जन्मकुंडली या ज्योतिषीय गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उसके दैनिक आचरण, व्यवहार और सोच में भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। यह सर्वविदित है कि जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल समय आने पर अवश्य मिलता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, उसका केवल रूप परिवर्तित होता है। विज्ञान भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल उसका स्वरूप बदलता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वह विचार के स्तर पर हो या व्यवहार के स्तर पर, एक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है और उपयुक्त समय पर सुख या दुःख के रूप में फलित होता है। यही कर्मफल सिद्धांत ग्रहों के प्रभाव से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन शास्त्रों में ग्रहों की शांति के लिए उपासना, यज्ञ, जप, तप, दान और रत्न धारण जैसे अनेक विधान बताए गए हैं। इन उपायों का अपना महत्व है, लेकिन अनुभव यह भी बताता है कि यदि हम केवल बाहरी

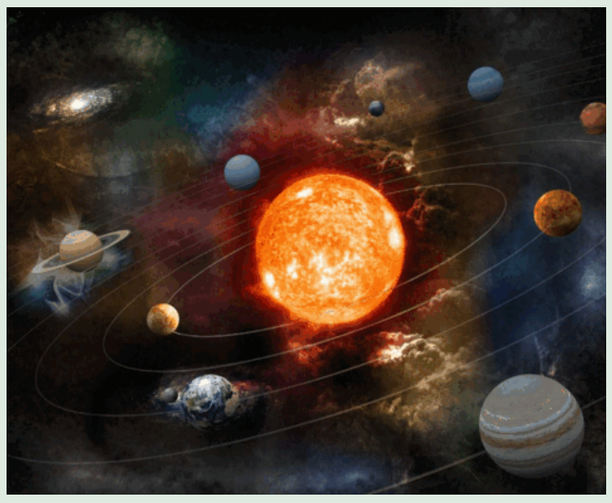

उपायों पर निर्भर रहें और अपने आचरण को न बदलें, तो ग्रहों की कृपा स्थायी नहीं बन पाती। वास्तव में ग्रह केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, बल्कि वे चेतना के स्तर पर इस पूरे चराचर जगत में व्याप्त हैं। वे पदार्थ, तत्व, वनस्पति, पशु-पक्षी और मनुष्य के संबंधों के माध्यम से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इसलिए यदि हम जड़ उपायों की अपेक्षा सीधे जीवों के साथ अपने संबंधों को सुधारें, तो ग्रह अत्यंत शीघ्र शांत हो सकते हैं। धर्मशास्त्रों में जीवन की सफलता के सूत्र संकेतों के रूप में दिए गए हैं। 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव' केवल नैतिक वाक्य नहीं हैं, बल्कि ग्रह शांति के अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावी उपाय हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं कि मात्र प्रणाम करने से, सदाचार का पालन करने से और नित्य वृद्धों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। यह वृद्धि केवल सामाजिक या मानसिक स्तर पर नहीं होती, बल्कि ज्योतिषीय स्तर पर भी ग्रहों की अनुकूलता को बढ़ाती है। जब मनुष्य जीवों के प्रति करुणा, परोपकार और सम्मान का भाव रखता है, तो उसकी कुंडली में रुष्ट ग्रहों की तीव्रता स्वतः ही कम होने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ग्रह का विशेष प्रभाव अवश्य रहता है। यह प्रभाव उसके स्वभाव, विचार, वाणी, निर्णय और जीवन की प्रमुख घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट दिखाई देता है। ऋषि-महर्षियों ने बताया है कि नौ ग्रह केवल आकाश में ही नहीं, बल्कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी अपने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहते हैं। सूर्य आत्मा के साथ-साथ पिता का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन के साथ माता का, मंगल पराक्रम के साथ छोटे भाई-बहनों का, बुध बुद्धि और वाणी के साथ मामा व बंधुओं का, बृहस्पति ज्ञान और धर्म के साथ गुरुजन, वृद्धों और बड़े भाई जैसे व्यक्तियों का, शुक्र ऐश्वर्य और भोग के साथ जीवनसाथी का, शनि दुःख और कर्म के साथ सेवक, श्रमिक और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। राहु और केतु समाज के उन वर्गों से जुड़े माने गए हैं, जो मुख्य धारा से अलग या उपेक्षित होते हैं। इस दृष्टि से यदि जीवन को देखा जाए, तो ग्रह शांति का मार्ग अत्यंत सरल और सहज बन जाता है। यदि सूर्य पीड़ित है, तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखें। चंद्रमा कष्ट दे रहा हो, तो माता और माता समान स्त्रियों की सेवा और भावनाओं का आदर करें। मंगल के अशुभ प्रभाव में छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध सुधारें। बुध की पीड़ा में मामा और संबंधियों के साथ मधुर व्यवहार करें। बृहस्पति के रुष्ट होने पर गुरुजन, वृद्धों और ज्ञानवान लोगों की सेवा करें। शुक्र के अशुभ होने पर जीवनसाथी को कष्ट न दें, बल्कि प्रेम, सम्मान और सहयोग दें, क्योंकि जीवनसाथी का अपमान सीधे ऐश्वर्य और सुख में कमी लाता है। शनि के कष्ट में श्रमिकों, सेवकों और निर्धनों के प्रति करुणा रखें। राहु के प्रभाव में अंगहीनों और समाज से बहिष्कृत लोगों की सहायता करें और केतु के लिए दीन-हीन, रोगी और असहाय लोगों की सेवा करें। अनुभव यह सिद्ध करता है कि यदि ग्रहों के प्रतिनिधि जीवों से हमारे संबंध बिगड़े हुए हों, तो पूजा-पाठ, जप-तप और दान भी अपेक्षित फल नहीं दे पाते। ग्रह चेतना के स्तर पर मनुष्य के आचरण को देखते हैं, न कि केवल उसके कर्मकांड को। जब आचरण शुद्ध होता है, विचार पवित्र होते हैं और व्यवहार करुणामय होता है, तब ग्रहों की कठोरता स्वतः पिघलने लगती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रहों को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय मनुष्य का स्वयं का आचरण है। जब जीवन सदाचार, प्रेम और सेवा की धारा में बहने लगता है, तब ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं और जीवन में शुभता, संतुलन और शांति का स्थायी वास हो जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

गुजरात पुलिस में नवनियुक्त 11,607 उम्मीदवारों को चयन पत्र प्रदान किए गए

चयन पत्र केवल सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन के पालन और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का अवसर है – मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को राज्य पुलिस बल में नए चयनित युवा पुलिस कर्मियों को प्रेरित करते हुए कहा कि चयन पत्र केवल सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन के पालन और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का अवसर है।

पुलिस बल की भर्तियों में उत्तीर्ण होकर लगभग 3,100 युवतियों सहित 11 हजार से अधिक युवा 'टीम गुजरात' शामिल हुए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में गांधीनगर में चयन पत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने इन युवा एवं उत्साहवर्धक नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मानव सेवा के धर्म और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सदैव कर्तव्यरत रहने की सीख दी।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कानून लागू कराने वाले पुलिसकर्मी को कर्तव्य पालन में मानवाधिकारों का सम्मान, संवैधानिक मूल्यों का पालन और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तब सहायता के लिए सबसे पहले पुलिस को याद करता है, यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने आचरण में विनम्रता, वाणी में मधुरता और कार्य में निष्ठा को पुलिस सेवा की प्राथमिकता बनाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए POLICE शब्द के विशेष अर्थ की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि P यानी पोलाइट – जनता के प्रति हमेशा विनम्र और सहृदयभाव के साथ काम करता हो,

O यानी ऑबिडिएंट जो हमेशा – अधिकारियों की आज्ञा में रहकर ड्यूटी निभाता हो, L यानी लोयल, भारत के संविधान, नियम-कानून के प्रति वफादार रहकर, उसका पालन करते हुए कार्य करता हो,

I यानी इंटेलिजेंट – सदैव सतर्क और बुद्धिचातुर्थ्य से कार्य करता हो,

C यानी करेजियस, किसी भी परिस्थिति में साहस न हारने वाला, हरेक फ्रंट पर वो लड़ने के लिए सज्ज हो, E यानी एन्थूजियास्टिक, उत्साही हो, जनता की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव हृदय में रखता हो।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिए पुलिस के इस मर्म को पुलिस बल में नए मिल होने वाले कर्मी भी 'नागरिक देवो भवः' के ध्येय के साथ चरितार्थ करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री ने स्मार्ट पुलिसिंग की प्रधानमंत्री की सोच को साकार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुलिसमॉडर्नाइजेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

उन्होंने जोड़ा कि राज्यव्यापी सीसीटीवी नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बॉडी वॉर्न कैमरा, साइबर आश्वस्त – इबर सेफ प्रोजेक्ट जैसे उपायों से राज्य का पुलिस बल टेक्नॉलोजी से सशक्त हुआ है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि नए शामिल हो रहे युवा टेक्नोसेवी हैं, जिससे अधिक क्षमता निर्माण होगा र

राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल की विशेष उपस्थिति

-:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल-:

- ▸▸ पुलिस बल में नए शामिल होने वाले कर्मी भी 'नागरिक देवो भवः' के ध्येय को साकार करेंगे
- ▸▸ जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तब सहायता के लिए सबसे पहले पुलिस को याद करता है
- ▸▸ राज्य सरकार पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है
- ▸▸ राज्यव्यापी सीसीटीवी नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बॉडी वॉर्न कैमरा, साइबर आश्वस्त – साइबर सेफ प्रोजेक्ट जैसे आयामों से पुलिस बल टेक्नॉलोजी संपन्न बना है
- ▸▸ जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आए, तो उसके दुःख में सहभागी बनकर पूरे दिल से सहायक होना– उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

विकसित भारत 2047 में विकसित-सुरक्षित-समृद्ध गुजरात लीड लेगा।

नवनियुक्त 11,607 उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस का अभिन्न अंग बनने के साथ वर्दी के रूप में आप सभी को समाज की बुराइयों को मिटाने की शक्ति मिली है। यह वर्दी हमें दिन-रात, सर्दी-गर्मी, त्यौहार या प्राकृतिक आपदा जैसी किसी भी कठिन परिस्थिति में जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहने की शक्ति देती है।

उन्होंने कहा कि आप सभी नवनियुक्त उम्मीदवार नई ऊर्जा और नए जोश के साथ ऐसा कार्य करें, जिससे वर्दी की गरिमा और सम्मान निरंतर बढ़े।

जब भी कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आपके पास आए, तो उसके दुःख में सहभागी बनकर पूरे दिल से उसकी सहायता करने का प्रयास करें।

उप मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार उम्मीदवारों से नियुक्ति के लिए जिले का चयन लिया जाएगा, ताकि उन्हें अपने मूल या निकटवर्ती जिले में नियुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त; उन्होंने जोड़ा कि जनवरी महीने के अंत तक नई भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

गुजरात पुलिस परिवार का हिस्सा बने जवानों को प्रेरणा देते हुए राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल ने कहा कि वर्दी धारण करने के बाद भी एक सामान्य नागरिक की तरह हमेशा अपने गांव, शहर और मित्रों से जुड़े रहना। पद से जुड़े संबंध केवल पद रहने तक ही सीमित होते हैं, लेकिन स्नेह और भावनाओं के संबंध सेवानिवृत्ति के बाद भी अटूट बने रहते हैं। आपके माता-पिता ने दिन-रात परिश्रम करके आपको इस मुकाम तक पहुँचाने का जो सपना देखा था, वह आज साकार हुआ है। उनके चरण स्पर्श कर अवश्य आशीर्वाद लेना।

-:उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी-:

- ▸▸ नवनियुक्तों को गुजरात पुलिस का अभिन्न अंग बनने के साथ वर्दी के स्वरूप में समाज की बुराइयों को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त हुई है
- ▸▸ राज्य में पहली बार उम्मीदवारों से नियुक्ति के लिए जिले का चयन मांगा जाएगा, निकट से निकट पोस्टिंग मिल सके ऐसे प्रयास
- ▸▸ जनवरी महीने के अंत तक नई भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नीरजा गोटरू और उनकी टीम ने बिना किसी शिकायत के समग्र भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पिछले एक महीने में विभिन्न विभागों में लगभग 40 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी गई हैं।

मुख्य सचिव श्री दास ने कहा कि जब नागरिक आपके पास आते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी केवल कानून का पालन करवाने की ही नहीं, बल्कि न्याय और मानवता की रक्षा करने की भी होती है। पुलिस की वर्दी केवल सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जन विश्वास, ईमानदारी और अनुशासन का प्रतीक है तथा नागरिकों के मन में सुरक्षा का छाप स्थापित करता है। उन्होंने जोड़ा कि कानून की रक्षा के लिए कठोर होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ-साथ मानवता और संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है। इस प्रकार समाज की शांति और सुरक्षा के लिए आपका योगदान अमूल्य है।

गुजरात पुलिस के महानिदेशक श्री विकास सहाय ने पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूर्ण करने के लिए गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि जब हम 'विकसित भारत - विकसित गुजरात' के संकल्प की परिकल्पना करते हैं, तो वह तभी संभव हो सकती है जब नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षा की अनुभूति हो। नागरिकों में सुरक्षा और संरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए गुजरात पुलिस वर्षों से प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसी कार्य के परिणामस्वरूप गुजरात मॉडल की चर्चा न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी हो रही है।

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ नीरजा गोटरू ने गुजरात पुलिस में चयनित नए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में राज्यभर से 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया था। शारीरिक परीक्षा पूर्ण होने के बाद 2.45 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी, जिनमें से 32 हजार से अधिक उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद प्रोविजनल सूची तैयार कर लोक रक्षक कैडर में कुल 11,899 उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया की गई, जिनमें से 8,782 पुरुष और 3,117 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बायोमेट्रिक सहित विभिन्न टेक्नॉलोजी के उपयोग से पारदर्शी रूप से आयोजित की गई।

इस चयन पत्र वितरण समारोह में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, पुलिस महानिदेशक (सीआईडी क्राइम एंड रेलवे) डॉ. के.एल.एन. राव, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर श्री ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, श्री राजू भार्गव, गृह सचिव सुश्री निपुणा तोरवणे, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग में भर्ती हुए उम्मीदवार उपस्थित रहे।

तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में संशोधन

(जीएनएस)। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पश्चिम रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी टिकट बुकिंग के समय यात्री द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा तथा ओटीपी के सफल सत्यापन के पश्चात ही टिकट जारी किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली पहले ही पश्चिम रेलवे से प्रारंभ होने वाली 21 ट्रेनों में लागू की जा चुकी है। अब यह ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 24 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित चार और ट्रेनों में भी लागू की जा रही हैः-

1. ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस – श्री गंगानगर एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस – बरौनी एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद – सहरसा एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 22956 भुज – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

यह नई प्रणाली कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग के समय एक वैध एवं सुगम मोबाइल नंबर अवश्य प्रदान करें, ताकि ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह करती है।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 20/21 दिसम्बर, 2025 की रात्रि से प्रारंभ होकर 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोरीवली में अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) पैनल के कमीशनिंग कार्य हेतु 26 एवं 27 दिसम्बर, 2025 को 23:00 बजे से 07:00 बजे तक एक मेजर नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 26 दिसम्बर, 2025 को 23:00 बजे से 27 एवं 28 दिसम्बर, 2025 की मध्यरात्रि तक कांदिवली और दहीसर के बीच डाउन फास्ट लाइन पर गति प्रतिबंध भी लागू रहेगा।

इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी तथा कुछ बोरीवली/अंधेरी लोकल ट्रेनें गोरेगांव तक ही चलाई जाएंगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

परिशिष्ट–I: 26/27 दिसम्बर, 2025 को ब्लॉक के दौरान गोरेगांव तक चलाकर वहीं से रिटर्न की जाने वाली ट्रेनें।

परिशिष्ट–II: 26/27 दिसम्बर, 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनें।

परिशिष्ट–III: 27 दिसम्बर, 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनें।

नोटः उपनगरीय लोकल ट्रेनों पर पड़ने वाले प्रभाव की सूचना यथासमय दी जाएगी। 31 दिसम्बर, 2025 के लिए नववर्ष समारोह को ध्यान में रखते हुए असामान्य निरस्तीकरण न हों, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने भावनगर मंडल के कर्मचारी को संरक्षा पुरस्कार से किया सम्मानित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 11 कर्मचारियों को दिनांक 22.12.2025 को पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया। यह सम्मान नवंबर 2025 के दौरान ड्यूटी के समय उनकी असाधारण सतर्कता, सजगता एवं समर्पण के कारण संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सजगता एवं कर्तव्यनिष्ठा रेलवे सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और वे अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भावनगर मंडल के लाठीदड रेलवे स्टेशन पर कार्यरत श्री घनश्याम सी. (कांटेवाला) को रेल परिचालन की संरक्षा से संबंधित उच्च स्तर की प्रतिबद्धता एवं सतर्कता के लिए महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार (GM Safety Award) से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 20.11.2025 को लाठीदड स्टेशन से एक मालगाड़ी पास थ्रू हो रही थी। उसी दौरान समपार फाटक पर तैनात श्री घनश्याम सी. (कांटेवाला) ने मालगाड़ी के सातवें एवं आठवें वैगन में हॉट एक्सल के कारण पहियों के अत्यधिक गर्म (रेड हॉट) होने की स्थिति को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बिना विलंब किए गेट फोन के माध्यम से स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने तत्परता से वॉकी-टॉकी के माध्यम से लोको पायलट को जानकारी दी, जिसके फलस्वरूप गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रोक दिया गया। इसके बाद सहायक लोको पायलट द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई और स्थिति सामान्य होने पर मालगाड़ी को गंतव्य के लिए सुरक्षित रूप से रवाना किया गया। भावनगर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने श्री घनश्याम सी. (कांटेवाला) को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई दी तथा कहा कि कर्मचारी की त्वरित सोच, सतर्कता एवं जिम्मेदाराना कार्यशैली के कारण एक संभावित गंभीर दुर्घटना को समय रहते टालना संभव हो सका। उन्होंने इसे रेल संरक्षा के प्रति भावनगर मंडल की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी - जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

(जीएनएस)। **1.प्रस्तावना:** विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप समृद्ध एवं सुदृढ़ ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ाकर तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान कर; एक ग्रामीण विकास रूपरेखा स्थापित करने के लिए अधिनियम।

2.विकसितभारतकेदृष्टिकोणके अनुरूपबढ़ीहुईआजीविकागारंटी: अकुशल शारीरिक श्रम करने इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी।

3.अधिनियमकेअंतर्गतशुरूकिएजानेवालेकार्य: इस विधान के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले सभी कार्य एवं परियोजनाएँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का अंग होंगी, जिनमें जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूलभूत अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के शमन हेतु कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.कार्यों की आयोजना: कार्यों की आयोजना विकसित ग्राम पंचायत आयोजना के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इन्हें पीएम गति–शक्ति सहित राष्ट्रीय स्थानिक योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। पंचायतों की भौगोलिक स्थिति, नगरीकरण की दिशा में प्रगति आदि पर आधारित उनकी विविध विकासात्मक आवश्यकताओं को योजना निर्माण के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

5.कृषि के व्यस्ततम समय के दौरान पर्याप्त कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना: ग्रामीण कार्यबल के लिए बढ़ाई गई मजदूरी-रोजगार गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से बुवाई और कटाई के व्यस्ततम समय के दौरान, कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में, अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर साठ दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान होगा, जिसके अंतर्गत बुवाई एवं कटाई की व्यस्ततम समयावधि को सम्मिलित किया जा सकेगा तथा इस अवधि में इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कार्य नहीं किए जाएंगे।

6.योजनाकास्वरूप: यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार, राज्य अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छह माह के भीतर योजना को अधिसूचित करेंगे।

7.वित्तपोषणपद्धतिः केन्द्र सरकार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के बीच निधि-साझेदारी की पद्धति पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रोंके लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगी।

8.राज्यों को मानक आधारित आवंटन: केन्द्र सरकार, वस्तुनिष्ठ मानकों वाले एक संयुक्त सूचकांक के आधार पर प्रत्येक राज्य को मानक आधारित आवंटन करेगी और मानक आवंटन से अधिक व्यय की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी।

9.विशेषछूट: प्राकृतिक आपदाओं अथवा असाधारण परिस्थितियों के समय, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए, विशेष छूट की अनुमति होगी, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके एवं राहत हेतु प्रावधानों में अस्थायी संशोधन किया जा सके।

10.कार्यान्वयन संरचना: राष्ट्रीय स्तर की एक संचालन समिति योजना का समग्र पर्यवेक्षण करेगी तथा मानक आवंटनों के अनुमोदन एवं अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य संचालन समिति को राज्य में योजना के कार्यान्वयन का क्षेत्राधिकार होगा तथा यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट पर्यवेक्षण, निगरानी एवं नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

11.जिला कार्यक्रम समन्वयक: जिला कार्यक्रम समन्वयक,जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत सभी कार्यकलापों के योजना-निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी एवं समन्वय के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा, जिसमें संबंधित सभी लाइन विभागों एवं प्राधिकरणों के साथ समन्वय शामिल होगा। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें यथा विहित रोजगार मांगों की पूर्ति एवं प्रबंधन, कार्यस्थलों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण तथा सहभागितापूर्ण योजना-निर्माण प्रक्रियाओं का सुगमीकरणसम्मिलित है। ग्राम पंचायत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करने तथा अधिनियम में विहित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगी।

12.पंचायतीराज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका: ग्राम पंचायत की प्राथमिक कार्यान्वयन भूमिका होगी तथा वह श्रमिकों का पंजीकरण करने, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी। ग्राम सभा नियमित सामाजिक अंकेक्षण भी करेगी। मध्यवर्ती पंचायतें,ब्लॉक-स्तरीय आयोजना, प्रस्तावों के समेकन एवं अभिसरण के सुगमीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगी। जिला पंचायतें, एक समर्पित संचालन समिति के माध्यम से, समग्र पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगी तथा समेकित जिला योजनाएँ तैयार करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) की सहायता करेंगी।

13. मजदूरी दर: अकुशल शारीरिक कार्यों हेतु मजदूरी दरें इस विधान के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। पृथक दरें अधिसूचित किए जाने तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दरें लागू मानी जाएंगी।

14. बेरोजगारी भत्ता: यदि किसी ग्रामीण परिवार को, मांग प्रस्तुत करने के पश्चात, निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार अनुसूची–II में विहित दरों एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी।

15. पारदर्शिता एवं जवाबदेही: पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी आधारित (स्पैटियल टेक्नालॉजी) आयोजना, मोबाइल एवं डैशबोर्ड आधारित निगरानी तथा साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों के माध्यम से प्रावधान किए जाएंगे। सामाजिक अंकेक्षण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

8,800 से अधिक जहाज़ रीसाइक्लिंग और 32% वैश्विक योगदान के साथ अलंग बना शिप रीसाइक्लिंग का "ग्रीन मॉडल"

- ▸▸ 2025-26 की शुरुआत से ही जहाज़ों के आगमन में दिखी तेजी, 13% की वृद्धि दर्ज
- ▸▸ अगले 10 वर्षों में 15,000 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग करने का महत्वाकांक्षी विज़न
- ▸▸ GMB के 1224 करोड़ के मास्टर प्लान से अलंग की शिप रीसाइक्लिंग क्षमता होगी दोगुनी
- ▸▸ आगामी VGRC में कच्छ और सौराष्ट्र के मंच से अलंग की 40 वर्षों की उपलब्धियों का होगा वैश्विक प्रदर्शन

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का दूसरा संस्करण जनवरी 2026 में राजकोट में होने जा रहा है जहाँ राज्य अपनी बढ़ती समुद्री ताकत को वैश्विक मंच पर अधिक मजबूती से पेश करेगा। इस आयोजन के केंद्र में है अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड, जिसे गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के नेतृत्व में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार ने पारदर्शी शासन, ठोस नीतियाँ, कड़े सुरक्षा मानक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को अपनाया है। इन सब प्रयासों के चलते अलंग आज केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की समुद्री विकास यात्रा का एक सशक्त और प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है।

अब तक 8,800 से अधिक जहाज़ों की

हुई रीसाइक्लिंग, प्राप्त सामग्री का 99.95 प्रतिशत का हो रहा पुनः उपयोग

अलंग विश्व के सबसे बड़े शिप रीसाइक्लिंग बाजारों में से एक है और वैश्विक शिप रीसाइक्लिंग क्षेत्र में 32% का योगदान देता है। अब तक यहाँ 8,800 से अधिक जहाज़ों का सुरक्षित और नियमित रीसाइक्लिंग किया जा चुका है। इन जहाज़ों से प्राप्त सामग्री का लगभग 99.95% पुनः उपयोग में लाया जाता है जिससे अलंग शिप रीसाइक्लिंग में उभरता हुआ "ग्रीन मॉडल" बन गया है।

रीसाइक्लिंग सामग्री का अधिकतम पुनःउपयोग होने के कारण अलंग में कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए स्थिर व्यवसाय के अवसर मौजूद हैं। स्क्रैप प्रोसेसिंग, स्टील रोलिंग, मशीनरी रिफर्बिशमेंट, ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में लगातार आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसर विकसित होते हैं।

इतना ही नहीं, अलंग में वर्तमान में 128 में से 115 प्लॉट पूरी तरह "हांगकांग कन्वेंशन (HKC) कम्प्लायंट" हैं, और जून 2025 से HKC के वैश्विक स्तर पर लागू होने के साथ ही अलंग को विश्व के सबसे विश्वसनीय ग्रीन रीसाइक्लिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली है।

2025-26 की शुरुआत से ही जहाज़ों के आगमन में दिखी तेजी, 13% की वृद्धि दर्ज

वर्ष 2024-25 के दौरान वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अलंग ने अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया और 113 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग किया। वर्ष 2025-26 की शुरुआत में जहाज़ों के आगमन में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने से क्षेत्र में सकारात्मक गति देखने को मिल रही है।

इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने 2025 में अलंग के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसके तहत आने वाले 10 वर्षों में 15,000 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग करने का मिशन भी रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा हेल्थकेयर, श्रमिक सुविधाएँ, समुद्री कौशल प्रशिक्षण और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को और मजबूत करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है।

GMB के 1224 करोड़ के मास्टर प्लान से अलंग की शिप रीसाइक्लिंग क्षमता होगी दोगुनी

भविष्य में बढ़ते शिप रीसाइक्लिंग वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (GMB) ने लगभग 1224 करोड़ की लागत से अलंग का मास्टर प्लान पूरा कर लिया है।

पश्चिम रेलवे
अहमदाबाद मंडल

क्विक वाटरिंग अरेंजमेंट के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के लिए ठेके का काम

ई-निविदा सूचना संख्या: DRM (M) ADI/38 /2025-26 दिनांक 22.12.2025 निम्नलिखित कार्य के लिए योग्य ठेकेदारों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का नाम:** पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में महेसाणा स्टेशन (MSH) और भीलड़ी (BLDI) स्टेशन पर क्विक वाटरिंग अरेंजमेंट के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के लिए 03 साल की अवधि के लिए ठेके का काम। **निविदा संख्या: M/233/CAMC/QWA/MSH/BLDI कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 2689992.00/- (केवल छब्बीस लाख नवासी हज़ार नौ सौ बानवे रुपये) **बयाना जमा राशि (अर्नेस्ट मनी) :** ₹ 53800.00/- (केवल तिरपन हज़ार आठ सौ रुपये) **निविदा बंद होने और खुलने की तारीख और समय:** 13/01/2026 को 13:00 बजे बंद होगा और 13/01/2026 को 13:30 बजे खुलेगा **वेबसाइट का विवरण नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का पूरा विवरण देखा जा सकता है और निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय का पता:** मंडल रेल प्रबंधक (मैकेकेनिकल), (प. रेलवे) दूसरी मंज़िल, मैकेनिकल ब्रांब्रांच, चामुंडा ब्रिज के पास, नरोडा रोड, पोस्ट सैजपुर बोघा, अहमदाबाबाद - 382345 http://www.ireps.gov.in

ADI 237

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

अटल नेतृत्व, अविरत विकास

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के जरिये राज्य के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है शिक्षा के साथ पोषण

▸▸ गुजरात सरकार की संवेदनशील योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है : अहमदपुर प्राथमिक शालाचार्य

▸▸ योजना अंतर्गत बच्चों को दिया जाता है सुखडी, चना चाट, मिक्स दलहन, मिलेट का अल्पाहार

▸▸ मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना द्वारा प्रधानमंत्री के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है गुजरात सरकार

(जीएनएस)। गांधीनगर : देश में सुशासन के मूल्यों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सुशासन के मूल्यों का अनुकरण करते हुए नागरिकों के सर्वांगीण कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें एक महत्वपूर्ण योजना है : मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, जो बच्चों की शिक्षा के साथ उनका पोषण भी सुनिश्चित करती है। इस योजना का लाभ गुजरात के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा के साथ उनके पोषण पर भी बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के अलावा; मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत ताजा एवं पौष्टिक नाश्ता दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ा है और साथ ही बच्चों में पोषण के स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त; सरकारी स्कूलों में आधुनिक क्लासरूम, पानी, बिजली, शौचालय, स्वच्छता, ट्रांसपोर्टेशन सहित सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कोई कमी न रह जाए; इसके लिए राज्य सरकार सदैव कटिबद्ध है।"

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना ने सुशासन को दी नई दिशा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सुशासन, सेवा एवं विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सुशासन को नई दिशा दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर, 2024 को 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुपोषित गुजरात मिशन अंतर्गत सरकारी एवं अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को पीएम पोषण योजना के तहत दिए जाने वाले दोपहर के भोजन के अलावा पौष्टिक अल्पाहार भी मिले।

विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति से लेकर उनके पोषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

गांधीनगर की देहगाम तहसील की अहमदपुर प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना का लाभ मिल रहा है। यह योजना किस प्रकार बच्चों के लिए लाभदायी सिद्ध हुई है; इस संबंध में शाला के आचार्य श्री हसमुखभाई पटेल ने कहा, "मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू होने के बाद विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति से लेकर उनके पोषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में माता-पिता रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर जाया करते हैं। ऐसे में बच्चों को भोजन किए बिना स्कूल में आना पड़ता है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू होने से पहले स्थिति ऐसी थी कि कई बच्चे नियमित स्कूल नहीं आते और उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता। यह योजना शुरू होने के बाद विद्यार्थी नियमित स्कूल आने लगे हैं। इतना ही नहीं; इस योजना के कारण कुपोषित बच्चों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। विद्यार्थियों को अल्पाहार में दलहन (कठोळ) दिया जाता है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास भी हो रहा है। गुजरात सरकार की यह संवेदनशील योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।"

मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना : 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है कैलोरी-प्रोटीनयुक्त अल्पाहार

पीएम पोषण योजनांतर्गत समाविष्ट सभी स्कूलों में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी 'मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना' अंतर्गत नियमित लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को औसत 200 किलो कैलोरी तथा 6 ग्राम प्रोटीन से युक्त पौष्टिक अल्पाहार दिया जाता है। हाल में राज्य के लगभग 32,265 प्राथमिक विद्यालयों के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कैलोरी-प्रोटीनयुक्त अल्पाहार मिल रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है गुजरात सरकार

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना अंतर्गत बच्चों को सुखडी (आटा-घी और गुड़-चीनी से बनने वाला खाद्यान्न), चना चाट, मिक्स दलहन, मिलेट का अल्पाहार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के लिए 617.67 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गुजरात पीएम पोषण योजना अंतर्गत भोजन के अलावा; बालवाटिका से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को अल्पाहार देने का निर्णय लेने वाला अग्रिम राज्य है। गुजरात सरकार इस पोषणोन्मुखी योजना के क्रियान्वयन द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के ध्येय को साकार कर रही है।

लिस्टिंग के पहले ही दिन KSH इंटरनेशनल के शेयर को झटका, निवेशकों की उम्मीदों पर फिरा पानी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मैग्नेट वाइंडिंग वायर निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर की शेयर बाजार में एंट्री उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही। मंगलवार को कंपनी का शेयर अपने निर्गम मूल्य से नीचे फिसलते हुए सूचीबद्ध हुआ, जिससे शुरुआती निवेशकों को झटका लगा। 384 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयर करीब चार फीसदी गिरावट के साथ बाजार में आया और पहले ही दिन कमजोरी के संकेत देने लगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों प्रमुख शेयर बाजारों पर केएसएच इंटरनेशनल का शेयर 370 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से लगभग 3.64 फीसदी कम है। लिस्टिंग के कुछ ही समय बाद बिकवाली का दबाव और बढ़ गया। बीएसई पर शेयर 7.55 फीसदी की गिरावट के साथ 355 रुपये तक लुढ़क गया, जबकि एनएसई पर इसमें 7.81 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और भाव 354 रुपये तक आ गया। कमजोर शुरुआत के चलते कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर करीब 2,437.85 करोड़ रुपये पर आ गया।

कंपनी ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के लिए 365 से 384 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। यह आईपीओ कुल 710 करोड़ रुपये का था, जिसमें 420 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए थे, जबकि 290 करोड़ रुपये की राशि बिक्री पेशकश यानी ओएफएस के जरिए जुटाई गई थी। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, लिस्टिंग के दिन शेयर में आई गिरावट के पीछे समग्र बाजार का दबाव, वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों की सतर्कता और मुनाफावसूली जैसे कारण माने जा रहे हैं।

केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी और यह कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी मैग्नेट वायर निर्माता मानी जाती है। खास बात यह है कि निर्यात के मामले में कंपनी की स्थिति काफी मजबूत है और इसे इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में गिना जाता है। 'केएसएच' ब्रांड के तहत कंपनी पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों को अपने उत्पाद सप्लाई करती है। इसके उत्पादों की मांग देश के भीतर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी बनी हुई है।

कंपनी अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और जापान समेत दुनिया के 24 देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है, जिससे इसकी वैश्विक मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्पादन क्षमता के लिहाज से भी कंपनी लगातार विस्तार की राह पर है। महाराष्ट्र के तलोजा और चाकन में केएसएच इंटरनेशनल की तीन फैक्ट्रियां पहले से संचालित हैं, जबकि अहिल्यानगर के सुपा क्षेत्र में एक नया प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उत्पादन और निर्यात दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि, मजबूत कारोबारी आधार और लंबी अवधि की विकास संभावनाओं के बावजूद शेयर की कमजोर लिस्टिंग ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। बाजार जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, नए प्लांट की प्रगति और घरेलू व वैश्विक मांग की स्थिति पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। फिलहाल, लिस्टिंग के पहले ही दिन आई गिरावट ने यह संकेत दे दिया है कि शेयर बाजार में सिर्फ नाम और इतिहास नहीं, बल्कि मूल्यांकन और बाजार की धारणा भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है।

विकसित बिहार के संकल्प को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी, सात निश्चय-3 के प्रचार को मिली नई रफ्तार

(जीएनएस)। पटना। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय-3 की जानकारी अब हर घर तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सात निश्चय-3 से जुड़ी सभी योजनाओं, उद्देश्यों और उपलब्धियों का प्रभावी, तथ्यात्मक और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता तक सरकार की मंशा और कार्य स्पष्ट रूप से पहुंच सके। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लेकर किसी भी प्रकार की गलत सूचना या अफवाह को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जैसे ही किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी सामने आए, उसका तुरंत खंडन किया जाए और सही तथ्यों को जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंपर्क विभाग की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच सेतु बनकर भरोसे और पारदर्शिता को मजबूत करना भी उसकी जिम्मेदारी है।

बैठक में बताया गया कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए मल्टी-प्लेटफॉर्म रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आउटडोर होर्डिंग्स, फ्लेक्स, चैटबॉट और डिजिटल इन्फ्लूएंसर्स के जरिए भी सात निश्चय-3 की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की योजना है, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिकतम लोगों तक सरकार की बात पहुंचे।

सात निश्चय-3 के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार ने 15 प्रमुख विषयों को केंद्र में रखा है। इनमें रोजगार सृजन, विधि-व्यवस्था, पर्यटन विकास, महिला सशक्तिकरण, पुलिस आधुनिकीकरण, नगर विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति, आधारभूत संरचना का विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी विषयों के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विकास केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग और हर जरूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं।

समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्राकृतिक आपदा, शांति व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपात स्थितियों में सही और प्रमाणिक सूचना का त्वरित प्रसार कर अफवाहों पर लगाम लगाने का काम किया जाता है। साथ ही जनता से मिलने वाले फीडबैक को विभिन्न माध्यमों से एकत्र कर संबंधित विभागों और सरकार तक पहुंचाया जाता है, ताकि नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बैठक के दौरान विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इनमें क्षेत्रीय प्रचार योजना, विशेष अंगीभूत योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, बिहार राज्य पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, बिहार डायरी एवं कैलेंडर का प्रकाशन, राज्य सूचना केंद्र का संचालन, आउटडोर पब्लिसिटी, पत्रकारों का प्रमाणीकरण और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए न केवल सरकारी सूचनाओं का प्रसार किया जा रहा है, बल्कि पत्रकारों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

सरकार ने सभी विभागों में जनसंपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जनसंपर्क पदाधिकारियों की तैनाती भी की है। ये अधिकारी अपने-अपने विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों की सही, तथ्यात्मक और अद्यतन जानकारी सक्रिय रूप से जनता तक पहुंचा रहे हैं।

फियो ने 9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों में उत्तरी भारत के उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 2025: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने 23 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में 9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों का आयोजन किया, ताकि भारत के निर्यात विकास में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया जा सके। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने प्रदान किए।

राज्य स्तर पर उत्कृष्टता को पहचानने और उच्च प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित, फियो के क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार उन उद्यमों का सम्मान करते हैं जिन्होंने उल्लेखनीय विकास, नवाचार, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दिखाई है। उत्तरी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं, भारत के निर्यात प्रदर्शन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके लचीलेपन और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने एक मजबूत और लचीला निर्यात प्रदर्शन बनाए रखा है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में कुल निर्यात में 5.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान मर्चेंडाइज निर्यात बढ़कर 292 बिलियन डॉलर हो गया। निर्यात सेक्टर की मज़बूती 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में और मदद करेगी। यह प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं, पेट्रोलियम उत्पादों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे क्षेत्रों में मजबूत विकास से प्रेरित है, जो भारत की निर्यात टोकरी के विविधीकरण और तकनीकी गहराई को उजागर करता है।

श्री अग्रवाल ने विदेश व्यापार नीति के माध्यम से एक स्थिर और सुविधाजनक

नीतिगत माहौल बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें व्यापार सुविधा, डिजिटलीकरण, अनुपालन बोझ में कमी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने व्यापार करने में आसानी और लेनदेन लागत को कम करने में पेपरलेस प्रणालियों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।वाणिज्य सचिव ने आगे कहा कि ट्रेड कनेक्ट पोर्टल को जारी रखते हुए, सरकार अनुपालन का बोझ और कम करने के लिए भारत ट्रेड नेट लाने की योजना बना रही है।

उन्होंने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के ज़रिए भारत की बढ़ती ग्लोबल ट्रेड भागीदारी के बारे में भी बताया, साथ ही यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इज़राइल, चिली, पेरू और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का भी ज़िक्र किया।

फियो अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनकी उद्यमी भावना और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा की सराहना की। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में रुकावटें, कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और प्रमुख बाज़ारों में आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारतीय निर्यातकों ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते अवसरों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, प्रोसेस्ड फूड, कृषि और ग्रीन टेक्नोलॉजी सहित क्षेत्रों में मज़बूत विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। रीजनल चेयरमैन (उत्तरी क्षेत्र), फियो श्री अरविंद गोयनका ने अपने स्वागत भाषण में, माननीय वाणिज्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और पुरस्कार विजेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कपड़ा, हथकरघा, कालीन, खेल के सामान, इंजीनियरिंग सामान, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्र के मज़बूत निर्यात आधार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्यों ने "ज़िलों को निर्यात हब" पहल के तहत राज्य निर्यात संवर्धन नीतियों और ज़िला निर्यात कार्य योजनाओं के साथ सक्रिय निर्यात-आधारित विकास पहलों को अपनाया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड सहित प्रमुख राज्य सामूहिक रूप से सालाना 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात करते हैं।

उन्होंने बताया कि क्लस्टर विकास, ओपीओडी -लिंक्ड निर्यात, लॉजिस्टिक्स पार्क, और निर्यातक सुविधा सेल जैसी केंद्रित पहलें एमएसएमई, कारीगरों और पहली बार निर्यात करने वालों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने के लिए सशक्त बना रही हैं। फियो के डीजी और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने अपने समापन भाषण में, निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को मज़बूत करने, उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने, विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स बनाने और बाज़ारों और उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G विस्तार, डिजिटल पेमेंट, स्थायी विनिर्माण और कुशल मैनपावर में भारत की ताकतें निर्यात वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाएंगी और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विज़न में योगदान देंगी।

9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 ने उन निर्यातकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित किया जिन्होंने भारत के व्यापार विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फियो ने निर्यातकों को सपोर्ट करने, नए अवसरों को बढ़ावा देने और भारत को एक प्रमुख ग्लोबल ट्रेडिंग देश के रूप में उभरने में मदद करने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सोना वायदा 1.38 लाख रुपये और चांदी वायदा 2.16 लाख रुपये के स्तर के पार पहुँचा: क्रूड ऑयल में 17 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 251048.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 36079.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 214960.4 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 34290 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2469.44 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 28410.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 138297 रुपये के भाव पर खूलकर, 138444 रुपये के ऑल टाइम हाई और 137826 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 136744 रुपये के पिछले बंद के सामने 1448 रुपये या 1.06 फीसदी की तेजी के संग 138192 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 1052 रुपये या 0.97 फीसदी की बढ़त के साथ 110045 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 153 रुपये या 1.12 फीसदी की बढ़त के साथ 13785 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 134900 रुपये के भाव पर खूलकर, 136888 रुपये के दिन के उच्च और 134900 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1452 रुपये या 1.08 फीसदी की बढ़त के साथ 136090 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 136136 रुपये के भाव पर खूलकर, 136504 रुपये के दिन के उच्च और 135388 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 134916 रुपये के पिछले बंद के सामने 1482 रुपये या 1.1 फीसदी की बढ़त के साथ 136398 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 214498 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 216596 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 214498 रुपये पर पहुंचकर, 212872 रुपये के पिछले बंद के सामने 2878 रुपये या 1.35 फीसदी की तेजी के संग 215750 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 2676 रुपये या 1.25 फीसदी की तेजी के संग 216277 रुपये प्रति किलो

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 36079.35 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 214960.4 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 28410.90 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34290 पॉइंट के स्तर पर

हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 2747 रुपये या 1.29 फीसदी बढ़कर 216317 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 4166.38 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 16.65 रुपये या 1.48 फीसदी बढ़कर 1138.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 3.45 रुपये या 1.14 फीसदी की तेजी के संग 306.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.3 रुपये या 0.81 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 55 पैसे या 0.3 फीसदी के सुधार के साथ 182.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3495.76 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5230 रुपये के भाव पर खूलकर, 5255 रुपये के दिन के उच्च और 5225 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 17 रुपये या 0.33 फीसदी की बढ़त के साथ 5240 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 15 रुपये या 0.29 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 5240 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 356.4 रुपये के भाव पर खूलकर, 362 रुपये के दिन के उच्च और 354.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 351.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 7.2 रुपये या 2.05 फीसदी की बढ़त के साथ 358.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 7.8 रुपये या 2.22 फीसदी बढ़कर 358.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 930 रुपये पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.13 फीसदी की तेजी के संग 932.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16596.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11814.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3528.73 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 189.19 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 17.98 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 430.47 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 364.97 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3120.04 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17143 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 81106 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 21900 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 328634 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 36008 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17028 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 41381 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 108078 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21424 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 44983 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 34319 पॉइंट पर खूलकर, 34351 के उच्च और 34236 के नीचले स्तर को छूकर, 381 पॉइंट बढ़कर 34290 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 5.9 रुपये की बढ़त के साथ 184 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 50 पैसे के सुधार के साथ 3.55 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 139000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 510.5 रुपये की बढ़त के साथ 1340.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 462 रुपये की बढ़त के साथ 2525 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1130 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7.95 रुपये की बढ़त के साथ 9.85 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 50 पैसे की नरमी के साथ 0.27 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.7 रुपये की गिरावट के साथ 147.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.2 रुपये की गिरावट के साथ 1.65 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 446 रुपये की गिरावट के साथ 515 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 215000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2354.5 रुपये की गिरावट के साथ 1869 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.94 रुपये की गिरावट के साथ 0.4 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.54 रुपये की गिरावट के साथ 9.04 रुपये हुआ।